केंद्र सरकार ने ईंधन आपूर्ति की मजबूत

बायोगैस प्लांट और गैस स्टेशनों को मिली मंजूरी

सीएनजी, सीबीजी और भंडारण क्षमता में विस्तार

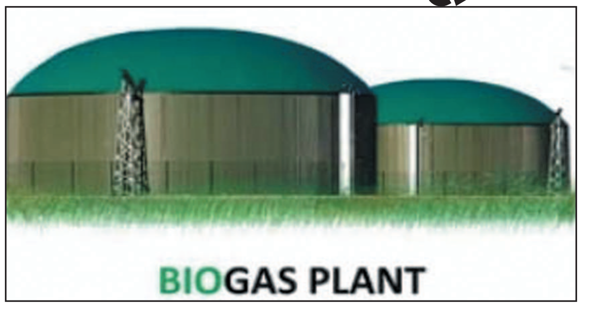

नई दिल्ली, 23 अप्रैल पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ रहे असर के बीच केंद्र सरकार ने देश में ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं.

सरकार ने स्पष्ट किया है कि ईंधन और गैस की आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए बायोगैस, सीएनजी और एलपीजी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाया जा रहा है, ताकि किसी भी संभावित कमी को रोका जा सके.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, हाल ही में बयालीस बायोगैस सिलेंडर भरने और भंडारण संयंत्रों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से चौदह संयंत्रों को लाइसेंस भी जारी कर दिया गया है. यह कदम देश में स्वच्छ ईंधन के उत्पादन और वितरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है. इसके साथ ही कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड बायोगैस स्टेशनों के विस्तार को भी प्राथमिकता दी जा रही है. पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन को कुल चार सौ सड़सठ आवेदन प्राप्त हुए थे, जिन्हें पच्चीस मार्च से इक्कीस अप्रैल के बीच प्राथमिकता के आधार पर निपटाया गया. इनमें से एक सौ सत्तावन मामलों को अंतिम लाइसेंस प्रदान किया गया, जबकि अड़तीस मामलों में नए स्टेशनों के निर्माण के लिए प्रारंभिक स्वीकृति दी गई है. सरकार का उद्देश्य इन प्रक्रियाओं को तेज कर ईंधन वितरण नेटवर्क को मजबूत करना है.ईंधन आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए कई सुरक्षा और प्रबंधन संबंधी उपाय भी लागू किए गए हैं.

> सरकार ने घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अमोनियम नाइट्रेट के निर्यात पर पूरी तरह रोक भी लगा दी है . इसके साथ ही एलएनजी को क्रायोजेनिक सिलेंडर में भरने की अनुमति देने के नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे आपूर्ति व्यवस्था अधिक लचीली और प्रभावी बन सके .

युवा उत्तराधिकारियों ने बढ़ाया कॉरपोरेट ग्रोथ

नई दिल्ली, 23 अप्रैल. भारत के कॉरपोरेट जगत में अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां पारिवारिक व्यवसायों की कमान तेजी से नई पीढ़ी के हाथों में आ रही है. ताजा रिपोर्ट के अनुसार, करीब पचास युवा उत्तराधिकारियों ने न केवल अपनी विरासत में मिली कंपनियों को संभाला है, बल्कि उन्हें नई रणनीति, आधुनिक तकनीक और आक्रामक विस्तार योजनाओं के जरिए कई गुना आगे भी बढ़ाया है.

हुरुन की रिपोर्ट बताती है कि इन युवा बिजनेस लीडर्स ने कंपनियों की कुल पूंजी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज कराई है. इससे न केवल कंपनियों का प्रदर्शन मजबूत हुआ है, बल्कि निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है. इन उत्तराधिकारियों को अब केवल पारिवारिक व्यवसाय का वारिस नहीं,

बीओबी ने शुरू किया वरिष्ठ नागरिक विशेष खाता

बुजुर्गों को स्वास्थ्य और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ

घर बैठे बैंकिंग और प्रीमियम सुविधाएं उपलब्ध

नई दिल्ली, 23 अप्रैल. देश के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष बचत खाता शुरू किया है. इस खाते का नाम वरिष्ठ नागरिक विशेष सम्मान खाता रखा गया है.

यह खाता विशेष रूप से साठ वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बनाया गया है, ताकि उन्हें सुरक्षित बैंकिंग सेवाओं के साथ-साथ स्वास्थ्य और जीवनशैली से जुड़ी अतिरिक्त सुविधाएं भी मिल सकें.

यह खाता उन ग्राहकों के लिए है जो अपने खाते में औसतन एक

लाख रुपये का बैलेंस बनाए रखते हैं. बैंक का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को एक ऐसा बैंकिंग अनुभव देना है जिसमें उनकी आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ उनकी दैनिक जरूरतों और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाए. इस विशेष खाते के साथ वरिष्ठ नागरिकों को कई स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं, जो एक स्वास्थ्य सेवा मंच के माध्यम से उपलब्ध होंगी.

इसके तहत खाताधारक को अपने परिवार के छह सदस्यों तक के लिए नि:शुल्क ऑनलाइन डॉक्टर परामर्श की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा दवाइयों की खरीद पर पंद्रह प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी और पैथोलॉजी जांच पर बीस प्रतिशत तक की छूट का लाभ भी मिलेगा.

> बैंक ऑफ बड़ौदा का यह कदम देश में बढ़ती वरिष्ठ नागरिक आबादी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है . विशेषज्ञों के अनुसार, इस प्रकार के विशेष खाते न केवल बुजुर्गों को बेहतर बैंकिंग सुविधा देते हैं, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी सुधारते हैं .यह विशेष खाता वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में सामने आया है, जिसमें बैंकिंग, स्वास्थ्य और जीवनशैली से जुड़ी सभी आवश्यक सुविधाएं एक साथ उपलब्ध कराई गई हैं .

डिजीहाट में मेट्रो टिकट सेवा शुरू

एक ऐप में सफर भी और खरीदारी भी

नई दिल्ली, 23 अप्रैल सरकार समर्थित डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजीहाट ने अपनी सेवाओं का विस्तार करते हुए दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु में मेट्रो टिकट बुकिंग सुविधा शुरू कर दी है. इस नई व्यवस्था के साथ उपयोगकर्ता अब एक ही ऐप के माध्यम से अपने दैनिक सफर की योजना बना सकेंगे, जिससे यात्रा अधिक सहज और सुविधाजनक हो जाएगी.

डिजीहाट का यह कदम उसे उन चुनिंदा प्लेटफॉर्म्स की श्रेणी में शामिल करता है, जो मेट्रो टिकटिंग के साथ-साथ ई-कॉमर्स और मोबिलिटी सेवाएं भी एक ही मंच पर उपलब्ध करा रहे हैं. कंपनी के अनुसार, प्लेटफॉर्म ने अब तक 20 लाख डाउनलोड का आंकड़ा पार कर लिया है और 30,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं का नेटवर्क तैयार किया है. यह वृद्धि इसके कम कमीशन और पारदर्शी संचालन मॉडल को दर्शाती है. डिजीहाट के मुख्य परिचालन अधिकारी राहुल विज ने कहा कि मेट्रो टिकटिंग सुविधा जुड़ने से प्लेटफॉर्म की मोबिलिटी सेवाएं और सशक्त होंगी तथा उपयोगकर्ताओं को एकीकृत डिजिटल अनुभव मिलेगा.

यह पहल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के व्यापक विजन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य देश में एक खुला डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम विकसित करना है. इस व्यवस्था के तहत बिचौलियों की भूमिका कम कर उपभोक्ताओं और विक्रेताओं के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है.

आईआईएमटी मेरठ में भव्य दीक्षांत समारोह आयोजित

उपराष्ट्रपति रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि

मेरठ, 23 अप्रैल आईआईएमटी विश्व विद्यालय, मेरठ के तृतीय वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन अत्यंत गरिमामय वातावरण में किया गया. इस अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे.

समारोह का मुख्य आकर्षण प्रतिष्ठित विद्वान डॉ. एच. एस. रावत को उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं सामाजिक सेवाओं के लिए 'विद्या वाचस्पति' की मानद उपाधि प्रदान किया जाना रहा, जिसे उपस्थित जनसमूह ने अत्यंत गर्व और सम्मान के साथ सराहा.

इस अवसर पर विश्वविद्यालय के चेयरमैन एवं कुलपति योगेश मोहन गुप्ता, प्रो चांसलर मयंक गुप्ता, तथा वाइस चांसलर दीपा शर्मा सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे. कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद एवं पूर्व भारतीय

जनता पार्टी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत बाजपेयी तथा उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धरमपाल सिंह भी शामिल हुए.

आध्यात्मिक एवं शैक्षणिक जगत की प्रमुख हस्तियों में स्वामी चिदानंद सरस्वती, ज्योतिष विभागाध्यक्ष एवं डीन आशा त्यागी, यूट्यूब गोल्ड मेडलिस्ट ज्योतिषाचार्य मनवेंद्र सिंह, पंडित नरेश शर्मा, हिमशिखा तथा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार वी. पी. राकेश की उपस्थिति ने समारोह की गरिमा को और बढ़ा दिया. दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई. यह आयोजन शिक्षा, संस्कृति और सम्मान का अद्भुत संगम साबित हुआ, जिसने सभी उपस्थित लोगों को प्रेरित किया.

पोस्ट ऑफिस योजना स्कीम देगी सीनियर सिटीजन को लाभ

नई दिल्ली, 23 अप्रैल बढ़ती महंगाई और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को लेकर चिंताओं के बीच पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम बुजुर्गों के लिए एक भरोसेमंद निवेश विकल्प बनकर उभर रही है.

यह योजना खासतौर पर रिटायर हो चुके लोगों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिससे उन्हें नियमित आय मिल सके और बुढ़ापे में पैसों की चिंता न रहे. इस स्कीम के तहत एकमुश्त निवेश पर हर महीने स्थिर आय का प्रावधान है, जो इसे सुरक्षित और आकर्षक बनाता है. सरकार समर्थित इस योजना में निवेश करने पर जोखिम बेहद कम होता है और रिटर्न भी तय दर पर मिलता है. वर्तमान में सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम पर आकर्षक ब्याज दर दी जा रही है, जिसके चलते निवेशकों को बेहतर मासिक आय हासिल हो सकती है. उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति इस योजना में अधिकतम निर्धारित सीमा तक निवेश करता है, तो उसे हर महीने लगभग 20,500 रुपये तक की आय प्राप्त हो सकती है. यह राशि बुजुर्गों के दैनिक खर्च, दवाइयों और अन्य जरूरतों को पूरा करने में काफी सहायक साबित होती है.

इस योजना की खास बात यह है कि इसमें निवेश की अवधि पांच साल की होती है, जिसे आगे तीन साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है. साथ ही, इसमें टैक्स लाभ भी मिलता है, जिससे यह और अधिक फायदेमंद हो जाती है. योजना में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग निवेश कर सकते हैं, जबकि कुछ शर्तों के साथ 55 से 60 वर्ष के बीच के रिटायर लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं. पोस्ट ऑफिस की इस योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है.

> सुरक्षित निवेश विकल्पों की तलाश कर रहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह योजना एक अच्छा विकल्प है . हालांकि, निवेश से पहले अपनी वित्तीय स्थिति और जरूरतों का आकलन करना जरूरी है . कुल मिलाकर, पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम उन लोगों के लिए उपयोगी साबित हो रही है, जो रिटायरमेंट के बाद स्थिर और सुरक्षित आय चाहते हैं .

सोना-चांदी के दामों में आई गिरावट

750 रुपए कम हुआ सोना

4500 रुपए सस्ती हुई चांदी

नई दिल्ली, 23 अप्रैल देश में शादी-ब्याह के सीजन के बीच घरेलू सर्राफा बाजार में गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 को सोना और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई.

चांदी के भाव में एक ही दिन में 4500 रुपये से अधिक की कमी आई है, जबकि सोने की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है, जिससे ग्राहकों को थोड़ी राहत मिली है.ताजा आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत में लगभग 750 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है और यह अब करीब 1,52,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं 22 कैरेट सोना भी सस्ता होकर 1,39,654 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है.

> दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में भी सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जहां 24 कैरेट सोना लगभग 1,52,000 रुपये से 1,52,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच और 22 कैरेट सोना लगभग 1,39,300 रुपये से 1,40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है .

चावल, चीनी, दालों के भाव टूटे, खाद्य तेलों में घट-बढ़

नयी दिल्ली, 23 अप्रैल. घरेलू थोक जिंस बाजारों में गुरुवार को चावल का औसत भाव गिर गया. चावल के साथ चीनी और दालों में भी नरमी देखी गयी. गेहूं में तेजी का रुख रहा, जबकि खाद्य तेलों के दामों में घट-बढ़ रही.

औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत 75 रुपये टूटकर 3,768 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गयी. गेहूं पांच रुपये महंगा हुआ और 2,779 रुपये प्रति क्विंटल बोला गया. आटे की कीमत 17 रुपये गिर गयी.दाल-दलहनों में नरमी रही. उड़द दाल 54 रुपये प्रति क्विंटल सस्ती हुई.

शेयर बाजारों में लगातार दूसरे दिन गिरावट

मुंबई, 23 अप्रैल ऑटो, बैंकिंग और आईटी सेक्टरों के दबाव में घरेलू शेयर बाजारों में गुरुवार को लगातार दूसरी गिरावट देखे गयी और बीएसई का सेंसेक्स एक प्रतिशत से ज्यादा लुढ़क गया.

सेंसेक्स 852.49 अंक (1.09 प्रतिशत) टूटकर 77,664 अंक पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक 205.05 अंक यानी 0.84 प्रतिशत नीचे 24,173.05 अंक पर रहा. यह दोनों सूचकांकों का 13 अप्रैल के बाद 10 दिन का निचला स्तर है. सुबह के कारोबार में छोटी कंपनियों में लिवाली थी, लेकिन बाद में वहां भी बिकवाली हावी हो गयी. वृहद बाजार में निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.71 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.67 प्रतिशत नीचे रहा.

जेडीयू सांसद गिरिधारी यादव की कुर्सी पर संकट

नई दिल्ली. जेडीयू सांसद गिरिधारी यादव की मुसीबत बढ़ने वाली हैं. अब ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी खुद की पार्टी जेडीयू ने ही उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, गिरिधारी यादव पर आरोप है कि उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान 'पार्टी विरोधी गतिविधियां' की और बेलहर से पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार किया.

गौरतलब है कि इसी सीट से उनके बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे. अब इसी मामले को लेकर जेडीयू ने कार्रवाई की मांग की है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जेडीयू सांसद गिरिधारी यादव को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है. यह शिकायत 25 मार्च को लोकसभा में जेडीयू नेता दिलेश्वर कामत ने की थी और बांका सांसद गिरिधारी यादव पर गंभीर आरोप लगाए थे.

दरअसल, जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामत ने आरोप लगाया कि गिरिधारी यादव जो 2010 से जेडीयू में हैं, उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान 'पार्टी विरोधी गतिविधियां' कीं और बेलहर से पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार किया. इसी सीट से उनके बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था. दिलेश्वर कामत ने बताया कि चाणक्य जेडीयू के मनोज यादव से बड़े अंतर से चुनाव हार गए. इसके बावजूद पार्टी ने गिरिधारी यादव के उस कदम को गंभीरता से लिया, जिसमें उन्होंने अपने बेटे को आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़वाया और उसके पक्ष में प्रचार भी किया. गिरिधारी यादव 2010 और 2015 में बांका सीट से पार्टी के टिकट पर दो बार जीत चुके हैं. दिलेश्वर कामत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर उन्हें एक विस्तृत नोटिस सौंपा. उन्होंने कहा कि पार्टी के निर्देश पर यह याचिका दायर की गई है.

> **गिरिधारी यादव का राजनीतिक रिकॉर्ड**
>
> गिरिधारी यादव का राजनीतिक रिकॉर्ड भी काफी मजबूत रहा है . उन्होंने 1996 से अब तक बांका लोकसभा सीट पर पांच बार जीत दर्ज की है . पहली बार वह जनता दल के उम्मीदवार के रूप में जीते थे, जबकि 2004 में उन्होंने आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीता . इसके बाद 2019 से अब तक वह जेडीयू के टिकट पर तीन बार जीत हासिल कर चुके हैं .

बहरामपुर में फिर गरजेगा रॉयल बंगाल टाइगर

क्या पिछली हार का बदला ले पाएंगे अधीर?

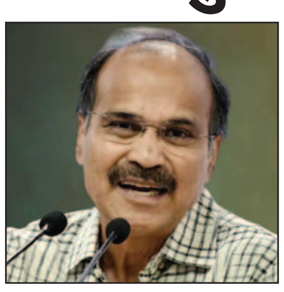

कोलकाता. पश्चिम बंगाल की राजनीति में जब भी मुर्शिदाबाद जिले की बात होती है, तो एक चेहरा बरबस ही आंखों के सामने आ जाता है. अधीर रंजन चौधरी, जिन्हें उनके समर्थक प्यार से बंगाल का शेर कहते हैं, एक बार फिर अपने पुराने गढ़ बहरामपुर की गलियों में पूरी ताकत के साथ सक्रिय नजर आ रहे हैं.

साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली अप्रत्याशित हार के बाद बहुत से लोगों ने यह मान लिया था कि शायद अधीर का सुनहरा राजनीतिक दौर अब समाप्त हो चुका है. कांग्रेस नेतृत्व ने 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें फिर से बहरामपुर मैदान में उतारकर यह साफ कर दिया है कि वे अभी थके नहीं हैं. यह चुनाव केवल एक विधानसभा सीट को जीतने की कवायद नहीं है, बल्कि अधीर रंजन के लिए अपनी खोई हुई साख और राजनीतिक पहचान को वापस पाने की एक बड़ी और निर्णायक जंग साबित होगी.

अधीर रंजन चौधरी का कद भारतीय राजनीति में बहुत ऊंचा रहा है और वे लगातार पांच बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं. बहरामपुर के आम मतदाताओं के साथ उनका रिश्ता दशकों पुराना है और वे यहां के हर छोटे-बड़े गांव और संकरी गलियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं. साल 2024 में पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान के हाथों मिली शिकस्त उनके लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं थी क्योंकि उस सीट पर उनका एकछत्र राज माना जाता था.

> **चुनावी समीकरणों को पलटने की बड़ी तैयारी**
>
> साल 2026 का बंगाल चुनाव कई मायनों में बहुत अलग होने वाला है क्योंकि कांग्रेस ने इस बार अकेले चुनाव लड़ने का साहसिक फैसला लिया है . ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में अधीर रंजन चौधरी की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उन पर न केवल अपनी सीट निकालने की जिम्मेदारी है बल्कि आसपास की अन्य सीटों पर भी असर डालने का भारी दबाव है .

क्या है राहुल की 16 की पहेली

नई दिल्ली. संसद के हर सत्र में राहुल गांधी कुछ न कुछ ऐसा करते हैं, जिसकी चर्चा देर तक होती है. इस बार भी उन्होंने 16 के अंक की एक पहेली छोड़ी है. उन्होंने संविधान के 131वें संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री जब भाषण देने खड़े हुए तो उनका आत्मविश्वास हिला हुआ था. राहुल ने कहा कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री को वैसे बोलते देखा तो अचानक ध्यान आया कि आज 16 तारीख है. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने 16 अप्रैल को बिल पर भाषण दिया था. राहुल ने 16 तारीख का जिक्र करके कहा कि सब कुछ इसी अंक में छिपा है. उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि किसी को समझ में आए तो वह उनको मैसेज करे.

उसके बाद संसद परिसर से लेकर सोशल मीडिया तक 16 के अंक की पहेली सुलझाने की होड़ मच गई. कुछ बहुत दिलचस्प टिप्पणियां देखने को मिली. कई लोगों ने कहा कि टीडीपी के 16 सांसद हैं लोकसभा में और राहुल का इशारा उनकी ओर था कि दक्षिण के राज्यों की दूसरी पार्टियों की तरह टीडीपी भी परिसीमन के कारण इस बिल का विरोध कर सकती है.

विशेष | **भ्रष्टाचार के आरोप, एंटी-इंकम्बेंसी और 'दीदी' का सुरक्षा कवच**

ममता की 15 साल की सबसे कठिन अग्निपरीक्षा

कोलकाता. पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक दशक से अधिक समय तक एकछत्र राज करने वाली ममता बनर्जी के लिए 2026 की चुनावी राह कांटों भरी नजर आ रही है. साल 2011 में वामपंथ के 34 साल पुराने किले को ढहाने वाली 'दीदी' आज खुद सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी-इंकम्बेंसी के चक्रव्यूह में फंसी दिखाई दे रही हैं.

विपक्षी दल, विशेषकर भाजपा, उनके शासन पर भ्रष्टाचार और लचर कानून-व्यवस्था का आरोप लगाकर घेराबंदी कर रहे हैं. हालांकि, अपनी सादगी भरी छवि और जमीन से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं के दम पर

ममता बनर्जी इस लहर को मोड़ने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं. ममता सरकार के लिए इस बार सबसे बड़ी चुनौती शासन से उपजी थकान और भ्रष्टाचार के दाग हैं.

शिक्षक भर्ती घोटाला, राशन वितरण, कोयला और पशु तस्करी जैसे मामलों ने सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया है, जिसे विपक्ष बड़ा चुनावी मुद्दा बना रहा है. इसके अलावा, आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना और संदेशखाली के विवादों ने महिला सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. शहरी मतदाताओं और मध्यम वर्ग में राजनीतिक हिंसा और चुनावी झड़पों को लेकर बढ़ता असंतोष टीएमसी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है.

बीजेपी का 'संकल्प पत्र' और गेमचेंजर योजनाओं की काट- भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ममता बनर्जी के 'कोर वोट बैंक' में सेंध लगाने के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया है. भाजपा ने टीएमसी की फेमस 'लक्ष्मी भंडार' योजना और बेरोजगारी भत्ते की राशि को दोगुना करने का वादा किया है. साथ ही, घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस और 6 महीने के भीतर यूसीसी लागू करने जैसे बड़े वादों के जरिए ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है. भाजपा का पूरा जोर कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार के नैरेटिव को घर-घर तक पहुंचाकर 'परिवर्तन' का संदेश देना है.

क्या नाराजगी बदल पाएगी सत्ता? - राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी-इंकम्बेंसी के संकेत जरूर हैं, लेकिन यह अभी तक 'लहर' का रूप नहीं ले पाई है.

> **ममता का सादगी, कल्याण और बांग्ला अस्मिता का सुरक्षा कवच**
>
> तमाम आरोपों के बावजूद, ममता बनर्जी की व्यक्तिगत लोकप्रियता आज भी उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है . नीले बॉर्डर वाली सफेद साड़ी और हवाई चप्पल वाली उनकी छवि जनता के बीच उन्हें एक 'एक्सेसिबल लीडर' के रूप में स्थापित करती है . 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनकी कुल चल संपत्ति महज 15.37 लाख रुपये है और उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, जो उनकी 'ईमानदार नेता' की छवि को पुख्ता करता है . साथ ही, कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार और स्वास्थ्य साथी जैसी योजनाओं का लाभार्थी वर्ग मजबूती से उनके साथ खड़ा है .